बजट भाषण

2023—2024

[भाग–क]

आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सदन के माननीय सदस्यगण,

1. मैं, आज दिल्ली विधानसभा में वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं इस जिम्मेदारी के लिए बहुत आभारी, सम्मानित और विनीत महसूस कर रहा हूँ। मुझे ज्यादा खुशी होती अगर यह बजट हमेशा की तरह हम सभी के आदरणीय पूर्व डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया जी द्वारा प्रस्तुत किया जाता। यह इस सरकार का 9वां और वित्त मंत्री के रूप में मेरा पहला बजट है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए बजट पेश करने का अवसर देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि बजट केवल संख्या और घोषणाओं का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि यह प्रत्येक आम आदमी की आशाओं और अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति है।

   यह बजट दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद की अभिवृद्धि और लोककल्याण की पवित्र और सच्ची भावना के साथ तैयार किया गया है। बजट तैयार करते समय उपनिषदों के इस अमर सन्देश को सामने रखा गया कि-

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद दुःख भाग भवेत।

2. माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले आठ वर्षों में दिल्ली ने अभूतपूर्व प्रगति देखी है। आज "**दिल्ली मॉडल**" शब्द हर देशवासी में आशा की एक नयी किरण जगाता है। साथ ही समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विश्वास देता है कि सरकार उनके परिवार के लिए विश्वस्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ़्त प्रदान करेगी। "**दिल्ली मॉडल**" एक गारंटी है कि अभूतपूर्व महंगाई के इस दौर में भी उन्हें पानी और 24 घंटे बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मुफ़्त में उपलब्ध होंगी। 100 से ज्यादा सेवाओं की

डोरस्टेप डिलीवरी तथा परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाओं जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टालरेंस नीति को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। अब आम आदमी को अपना काम करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के अंतहीन चक्कर नहीं लगाने पड़ते और न तो बिचौलियों की मदद लेनी पड़ती है। नागरिकों की सभी जरूरतों को समय पर और कुशलता से पूरा करने के लिए सरकार उनके दरवाजे तक पहुंचती है।

3. दिल्ली मॉडल का एक और पहलू, हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। दिल्ली न केवल राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले 2 करोड़ लोगों के लिए, बल्कि भारत के सभी 140 करोड़ लोगों के लिए गौरव का स्रोत है। दिल्ली 21वीं सदी में भारत की प्रगति और क्षमता का प्रतीक है और इसीलिए दिल्ली की सूरत और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है।

4. पिछले आठ वर्षों में दिल्ली सरकार ने कुछ ऐतिहासिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को पूरा किया है, जिसने दिल्ली का चेहरा बदल दिया है। 2018 में बनकर तैयार हुआ सिग्नेचर ब्रिज आज दिल्लीवासियों को गर्व का अहसास कराता है। सराय काले खां और आईएनए बाजार को जोड़ने वाले बारापुला फ्लाईओवर का दूसरा चरण भी 2018 में जाकर पूरा हुआ। ये दोनों परियोजनाएं पिछली सरकारों की लेटलतीफी के चलते लंबे समय तक लटकी रहीं। बारापुला फ्लाईओवर का तीसरा चरण भी जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। इस साल, आश्रम फ्लाईओवर और अंडरपास का काम भी पूरा हो गया, जिससे दिल्ली में करीब 4 लाख वाहनों का दैनिक आवागमन आसान हो गया। मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि पिछले आठ वर्षों में PWD ने 28 नए फ्लाईओवर, एलिवेटेड सड़कों और पुलों का निर्माण किया है, जिससे दिल्ली में आवागमन काफी आसान हो गया है।

5. इस सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए आधुनिक, विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने में निवेश किया है। पिछले आठ वर्षों में दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क का काफी विस्तार

हुआ है और लगभग दोगुना हो गया है। 1998 में दिल्ली मेट्रो का निर्माण शुरू होने के बाद से पहले 17 वर्षों में मार्च 2015 तक कुल 193 किमी रेल नेटवर्क और 143 मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया गया था। जबकि, पिछले आठ वर्षों में यानी 2015 से 2023 तक दिल्ली मेट्रो की नेटवर्क लंबाई दोगुनी होकर 390 किमी हो गई है और स्टेशनों की संख्या 286 हो गई है। इस अवधि में दिल्ली के सार्वजनिक बस नेटवर्क में भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। 2015 में 5,842 बसों से बढ़कर 2023 में 7,379 बसें हो गई हैं, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा हैं।

6. 2021-22 के देशभक्ति बजट में हमारी सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी, जिसने हर दिल्लीवासी को गर्व से भर दिया। सरकार ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर भव्य तिरंगा लगाने का वादा किया था। आज मैं बहुत गर्व के साथ यह साझा कर रहा हूं कि सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए दिल्ली को 'तिरंगों का शहर' बनाया। आज दिल्ली के आसमान में शान से लहराते तिरंगे को देखे बिना शायद ही कोई व्यक्ति राजधानी की किसी सड़क से गुजरता होगा।

7. अध्यक्ष महोदय, आने वाला वर्ष दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भारत के पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर रहने वाली हैं। पिछले आठ वर्षों में केजरीवाल सरकार ने कई ऐतिहासिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को पूरा किया है । इसके चलते आने वाला वर्ष दिल्ली को वैश्विक मंच पर एक साफ-सुंदर और आधुनिक शहर के रूप में खुद को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर भी प्रस्तुत करता है। इसलिए मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को

"साफ-सुंदर और आधुनिक दिल्ली"

के लिए समर्पित कर रहा हूं। **'साफ-सुंदर और आधुनिक दिल्ली'** हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है और यह हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी का 1400 किलोमीटर का मुख्य सड़क नेटवर्क है। इसके अपग्रेडेशन और सौंदर्यकरण के लिए परियोजना ला रहे हैं। यह दिल्ली या शायद किसी भी भारतीय शहर के इतिहास में सबसे बड़ी परियोजना होगी। इसके तहत सड़कों और फुटपाथों के पूरे नेटवर्क की मरम्मत और पुनर्निमाण किया जाएगा। इन्हें पैदल चलने वालों के अनुकूल बनाया जाएगा। सड़कों से लगे कच्चे हिस्सों में हरियाली सुनिश्चित करने से लेकर पूरे सड़क नेटवर्क की मशीन से नियमित सफाई और धुलाई की जाएगी। इससे दिल्ली की सड़कों की सूरत बदल जाएगी।

8. दिल्ली के परिवहन नेटवर्क के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार चौतरफा प्रयास कर रही है। इसके तहत दिल्ली के मौजूदा सड़क नेटवर्क के अपग्रेडेशन के अलावा हमारी सरकार 29 नए फ्लाईओवर, अंडरपास व पुलों का निर्माण करा रही है। साथ ही, हवाई अड्डों जैसे आधुनिक 3 विश्वस्तरीय आईएसबीटी और मेट्रो रेल नेटवर्क के चौथे चरण के विस्तार की दिशा में काम कर रही है। हम इस साल 1600 आधुनिक जीरो एमिशन (Zero Emission) इलेक्ट्रिक बसों की एक रिकॉर्ड संख्या शामिल करेंगे, जो 2023 के अंत तक दिल्ली के इलेक्ट्रिक बस बेड़े को भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ा बना देगा। हम 1400 नए मॉडर्न बस क्यू शेल्टर (BQS) की स्थापना भी करेंगे। डिजिटल स्क्रीन के साथ आधुनिक Passenger Information System (PIS) बसों के आगमन का समय प्रदर्शित करेगा। साफ और सुंदर यमुना के बिना साफ और सुंदर दिल्ली का सपना अधूरा है। अगले साल हम दिल्ली की सभी कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ियों तक सीवर नेटवर्क का तेजी से विस्तार करेंगे और साफ यमुना के विजन को हासिल करने के लिए अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमताओं को युद्धस्तर पर अपग्रेड करेंगे।

9. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के तीन कूड़े के पहाड़ पिछले कई दशकों से दिल्ली की छवि पर एक काला धब्बा रहे हैं। हालांकि कचरे के पहाड़ से निपटने का काम एमसीडी के दायरे

में आता है, लेकिन दिल्ली के लोगों की खातिर, हम एमसीडी के साथ मिलकर काम करेंगे और तीनों कूड़े के पहाड़ का अंत सुनिश्चित करने के लिए उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे।

10. ये सभी कदम उठाते हुए 21 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के पूंजीगत कार्यों के विशाल बजट के साथ 'साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली' बनाने के लिए एक स्पष्ट और व्यापक योजना प्रस्तुत की गई है। इससे दिल्ली पर हर भारतीय को गर्व होगा।

दिल्ली का आर्थिक परिदृश्य

11. अगले वर्ष के बजट प्रस्तावों पर बातचीत करने से पहले मैं थोड़ी सी बात दिल्ली की अर्थव्यवस्था के बारे में करना चाहता हूं। दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ-साथ एक बड़ा कमर्शियल और आर्थिक केंद्र भी है। दिल्ली की आर्थिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसका विकास भारत की आर्थिक विकास योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय सेवाएं, वाणिज्यिक विकास और सरकारी क्षेत्रों का बड़ा योगदान है।

12. कोविड-19 के दौरान आई आर्थिक चुनौतियों से अब दिल्ली की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे उभर रही है और इसके चलते दिल्ली का GSDP प्रचलित बाजार मूल्यों पर वर्ष 2021-22 के 9,04,642 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 10,43,759 करोड़ रूपए रहने की संभावना है, जो 15.38 प्रतिशत अधिक है।

13. मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि वर्ष 2022-23 में दिल्ली की GSDP की वास्तविक वृद्धि दर 9.18 प्रतिशत रहने की संभावना है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि दर 7.0 प्रतिशत रहने का आकलन है। इसका अर्थ है कि हम महामारी पूर्व आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर पुनः पहुंच रहे हैं।

14. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 के दौरान दिल्ली की GSDP मौजूदा कीमतों पर 18.50 प्रतिशत और स्थिर कीमतों पर 9.14 प्रतिशत बढ़ी, जो कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के लिए किए गए प्रभावी उपायों को दर्शाती है।

15. राष्ट्रीय स्तर पर GDP में दिल्ली के वास्तविक GSDP का योगदान 2011-12 में 3.94 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 4.09 प्रतिशत होने का अनुमान है। जबकि दिल्ली देश की कुल आबादी का केवल 1.53 प्रतिशत है। मैं यह बताना चाहूंगा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में मुख्यतः सेवा क्षेत्र का योगदान है और प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में इसका योगदान 84.84 प्रतिशत है, जबकि सेकेंडरी क्षेत्र का योगदान 12.53 प्रतिशत और प्राइमरी क्षेत्र का 2.63 प्रतिशत है।

16. वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की प्रति-व्यक्ति आय बढ़कर 4,44,768 रुपए हो जाने की संभावना है। वर्ष 2021-22 में यह 3,89,529 रुपए थी। यह 2022-23 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 14.18 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत 1,72,000 रुपए से करीब 2.6 गुना ज्यादा है।

17. अध्यक्ष महोदय, ये सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में दिल्ली की अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करने में एक बड़ा योगदान दिया है, जिसका श्रेय सरकार के अभिनव और प्रगतिशील दृष्टिकोण को जाता है।

18. दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय भारत के सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है और 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सत्ता में आने के बाद से दिल्ली देश में सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी वाले राज्य के रूप में उभरा है। इससे पता चलता है कि न केवल दिल्ली के एक आम निवासी की औसत आय देश के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक है, बल्कि दिल्ली के सबसे गरीब लोगों की

न्यूनतम मजदूरी भी देश में सबसे अधिक है। यह दिल्ली के आर्थिक विकास मॉडल के केंद्र में है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जनता की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे और लोग अपनी आय के अनुसार विभिन्न वस्तुओं को खरीदने और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हों।

संशोधित अनुमान 2022-23

19. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए के अनुमोदित बजट अनुमान की तुलना में संशोधित बजट अनुमान, 72,500 करोड़ रुपए का है। 72,500 करोड़ रुपए का प्रस्तावित संशोधित अनुमान 2021-22 में 61,172 करोड़ रुपए के वास्तविक व्यय से 18.52 प्रतिशत अधिक है। संशोधित अनुमान राशि 72,500 करोड़ रूपये में राजस्व व्यय के लिए 53,296 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय के लिए 19,204 करोड़ रुपए शामिल हैं।

20. स्थापना व्यय और अन्य प्रतिबद्ध देयताओं के लिए 2022-23 के अनुमोदित बजट अनुमान 32,200 करोड़ रुपए से बढ़कर संशोधित अनुमान में 33,800 करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। स्कीम/परियोजनाओं के लिए संशोधित अनुमान 2022-23 में 38,700 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अनुमोदित बजट अनुमान में यह 43,600 करोड़ रुपए था।

वर्ष 2022-23 के लिए पूरक अनुदान मांगें

21. महोदय, वर्ष 2022-23 के दौरान संशोधित अनुमानों में 159.17 करोड़ रुपए की द्वितीय व आखिरी पूरक अनुदान मांग की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं, पूरक अनुदान मांगों के लिए सदन का अनुमोदन चाहता हूं।

22. अब, मैं इस सदन के समक्ष अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं-

<u>बजट अनुमान 2023-24</u>

23. हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का कुल व्यय 2014-15 के दौरान 30,940 करोड़ रुपए था। हमारी सरकार ने जून 2015 में 41,129 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट के साथ अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया था।

24. अत्यंत हर्ष के साथ मैं वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं, जो वर्ष 2014-15 के 30,940 करोड़ रुपए व्यय की तुलना में ढाई गुणा से अधिक है और वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान से 8.69 प्रतिशत अधिक है।

25. गौरतलब है कि 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपये के बजट अनुमान में राजस्व व्यय के तहत 56,983 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के तहत 21,817 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है। कुल बजट के हिस्से के रूप में पूंजीगत व्यय का हिस्सा भी इस साल के बजट में बढ़कर 27.68 प्रतिशत हो गया है। 21,817 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय 2014-15 में 7,430 करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय का लगभग तीन गुना है। 78,800 करोड़ रुपये के बजट में 35,100 करोड़ रुपये स्थापना और अन्य प्रतिबद्ध व्यय के लिए है और 43,700 करोड़ रुपये योजनाओं/प्रोग्राम्स और परियोजनाओं के लिए है।

26. अध्यक्ष महोदय, मैं यहां सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पिछले आठ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा करों और शुल्कों के केंद्रीय पूल से दिल्ली के वैध हिस्से को आवंटित करने के सौतेले व्यवहार के बावजूद दिल्ली के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। जहां अन्य राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए सभी करों का 42 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होता है, वहीं करों के केंद्रीय पूल से दिल्ली का हिस्सा वर्ष 2001-02 से वर्ष 2022-23 तक 325 करोड़ रुपए पर स्थिर रहा है। यह ना के बराबर है, क्योंकि दिल्ली हर साल केंद्र सरकार को आयकर में 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देती है और करों के केंद्रीय पूल में दिल्ली का वैध हिस्सा लगभग 6 हजार 400 करोड़ रुपए है। और अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार ने करों के केंद्रीय पूल से दिल्ली

के हिस्से के रूप में 325 करोड़ रुपये भी शून्य कर दिए हैं। यह दिल्ली की जनता के साथ आर्थिक भेदभाव और घोर अन्याय है।

27. जून 2022 में GST मुआवजा कार्यक्रम की समाप्ति के कारण भारत के कई राज्यों की तरह, दिल्ली भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इस कारण राजस्व घाटा 12,000 करोड़ रुपये सालाना तक होने की उम्मीद है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव सहित कई कारणों से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी लाने वाले GST के वादे को पूरा नहीं किया जा सका है। परिणामस्वरूप राजस्व संग्रह में कमी होने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और समग्र विकास के लिए व्यय में भारी कमी आ सकती है। हमने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह अगले 5 वर्षों तक मुआवजा प्रदान करना जारी रखे, जब तक कि GST संग्रह 14 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर हासिल नहीं कर लेता।

28. वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट का वित्त पोषण 53,565 करोड़ रुपए कर राजस्व से, 1,050 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व से, 10,000 करोड़ रुपए लघु बचत ऋण से, 622 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियों से, 3802 करोड़ रुपए GST कंपनसेशन से, 3,167 करोड़ रुपए केंद्र प्रायोजित योजनाओं से और केवल 1,168 करोड़ रुपए भारत सरकार की अनुदान सहायता से और बाकी Opening Balance से जुटायी जाएगी।

<u>स्थानीय निकायों को वित्तीय सहयोग</u>

29. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार वर्ष 2023-24 के अनुमानित बजट में स्थानीय निकायों को 8241 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगी। इसमें से 2,659 करोड़ रुपए स्थानीय निकाय द्वारा योजनाओं/ कार्यक्रमों/परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संबद्ध राशि के रूप में होंगे, 2,492 करोड़ रुपए बेसिक टैक्स असाइंमेंट (BTA) के रूप में और 2,240 करोड़ रुपये की राशि स्थानीय निकायों को स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क

और एकमुश्त पार्किंग शुल्क के रूप में प्रदान की गयी है। उपरोक्त राशि में से 850 करोड़ रुपए स्थानीय निकायों को ऋण के रूप में दिए जाएंगे।

साफ-सुंदर और आधुनिक दिल्ली

30. अध्यक्ष महोदय, मैं अब दिल्ली को एक 'साफ़, सुंदर और आधुनिक' शहर में बदलने के लिए अपनी व्यापक योजना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जब कोई भी भारतीय विदेश जाता है, तो सबसे पहले उसे वहां की शानदार सड़कें और साफ-सुथरी व्यवस्था लुभाती हैं। वे उचित रोड मार्किंग, स्ट्रीट साइनेज और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ देखते हैं, जिसका उपयोग बच्चे या वरिष्ठ नागरिक या विकलांग भी आराम से कर सकते हैं। वे चारों ओर स्वच्छता का माहौल देखते हैं और यह सब उन्हें आश्चर्यचकित करता है। वे सोचते हैं कि "हमारे देश में ऐसी सड़के क्यों नहीं हैं? क्या ऐसा भारत में मुमकिन हो सकता है?"

31. अध्यक्ष महोदय, यही विचार हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के विज़न के पीछे भी था। तब हमने यूरोप की सड़कों की तर्ज पर दिल्ली में 8 किलोमीटर तक की लंबाई वाली 16 अलग-अलग सड़कों के पुनर्विकास और सौंदर्यकरण के लिए पायलट परियोजना शुरू की थी। विभिन्न प्रकार की सड़कें जो अलग अलग स्थितियों में थी, उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप अपग्रेड और सुंदर करने का यह एक प्रयास था। आपने दिल्ली में मोतीबाग से मायापुरी, मूलचंद जंक्शन से आश्रम चौक, राजघाट, लोधी रोड आदि क्षेत्रों में इन सड़कों को देखा होगा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ये पायलट प्रोजेक्ट बहुत सफल रहे हैं। इन पायलट रोड स्ट्रेच की तस्वीरें स्थानीय निवासियों की सेल्फी के साथ हर दिन सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में आ रही हैं। ये सड़कें स्थानीय निवासियों को गर्व की अनुभूति भी कराती हैं। इस सफल पहल ने साबित कर दिया है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर कहते हैं, 'ये हो तो सकता है, बस नीयत ठीक होनी चाहिए।'

32. महोदय, जब हम आने वाले वर्षों में देश के इतिहास में दिल्ली को 'साफ, सुंदर और आधुनिक शहर' में बदलने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी और व्यापक योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, तब हमारे मुख्यमंत्री जी के यही शब्द हमारे आदर्श सिद्धांत और हमारे मार्गदर्शक होंगे। हम इन योजनाओं को एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष में शुरू कर रहे हैं। इसी वर्ष में दिल्ली भारत के पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसके मद्देनज़र, मैं इस बजट में कई योजनाओं का प्रस्ताव कर रहा हूं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं-

i. PWD के संपूर्ण सड़क नेटवर्क के 1400 किलोमीटर का अपग्रेडेशन और सौंदर्यकरण
ii. दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 26 नये फ्लाईओवर/पुल/अंडरपास का निर्माण
iii. DMRC के सहयोग से 3 अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण
iv. नई 1600 प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करना, जिसमें 100 फीडर बसें भी शामिल हैं
v. दिल्ली के 57 मौजूदा बस डिपो का विद्युतीकरण
vi. दिल्ली में 3 विश्वस्तरीय ISBT, 2 आधुनिक बस टर्मिनल, 2 बहुमंज़िला बस डिपो और 9 नये बस डिपो का निर्माण
vii. दिल्ली में 1400 नए और आधुनिक बस क्यू शेल्टरों का निर्माण
viii. साफ यमुना के लिए छह सूत्रीय कार्ययोजना
ix. दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म करना

33. महोदय, मैं अब इन सभी योजनाओं का विवरण देने के लिए कुछ समय लेना चाहूंगा।

34. दिल्ली में, सड़कों की मरम्मत, रखरखाव और देखभाल की जिम्मेदारी कई एजेंसियों के पास है। अधिकांश एमसीडी (लगभग 12,703 किमी), एनडीएमसी (लगभग 1290 किमी)

और PWD (लगभग 1400 किमी) के पास है। दुर्भाग्य से एजेंसियों के बीच एक सामान्य दृष्टिकोण और समन्वय की कमी के कारण हम अक्सर देखते हैं कि सड़कें गंदी रहती हैं और पैदल यात्रियों को सड़को पर गड्ढों और टूटे फुटपाथों का सामना करना पड़ता है। हमारी कई सड़कों पर एक समान साइन बोर्ड और रोड मार्किंग नहीं है या सड़कों से सटे कच्चे हिस्से में बहुत सारी धूल है, जो चलते ट्रैफिक के कारण हवा में उड़ती रहती है। इससे गंभीर वायु प्रदूषण होता है।

35. दिल्ली में 16 सड़कों के कायाकल्प के लिए शुरू की गई पायलट परियोजना की सफलताओं के आधार पर दिल्ली सरकार ने PWD के तहत 1400 किलोमीटर सड़कों के अपग्रेडेशन और सौंदर्यीकरण के लिए एक व्यापक योजना बनाई है। इन सड़कों को दिल्ली की पहचान के रूप में भी जाना जाता है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन सभी सड़कों का अपग्रेडेशन और सौंदर्यकरण वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूरा कर लिया जाएगा। हमारा लक्ष्य इन सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक बनाना होगा। इस पहल के तीन प्रमुख बिंदु होंगे-

36. पहला- PWD के अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक सड़क पर ब्लैक टॉपिंग की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक दिल्ली में PWD के तहत पूरे 1400 किमी सड़कों में एक भी ऐसी सड़क नहीं होगी, जो टूटी हुई हो या उसमें गड्ढे हों। इतना ही नहीं, सभी PWD सड़कों पर स्वच्छ और सुंदर लेन मार्किंग की जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक, दिल्ली के लोगों को सभी PWD सड़कों पर, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, ट्रैफिक सिग्नल पर चमचमाती लेन के निशान और ज़ेबरा क्रॉसिंग दिखाई देंगे। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन लेन मार्किंग और जेब्रा क्रॉसिंग की चमक फीकी न पड़े। इसके लिए हर तीन माह में इसका रंग रोगन किया जाएगा। वही एजेंसी जो सड़क नेटवर्क का प्रारंभिक अपग्रेडेशन करेगी, अगले 10 वर्षों तक इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी, ताकि जवाबदेही बनी रहे।

37. दूसरा- पूरे 1400 किमी PWD सड़क नेटवर्क के साथ-साथ सभी फुटपाथों की पूरी तरह से मरम्मत की जाएगी और पैदल चलने वालों के लिए अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। इन सड़कों पर जहां कहीं भी सेंट्रल वर्ज है, उस सेंट्रल वर्ज की मरम्मत की जाएगी और इन सड़कों के किनारे या फुटपाथ पर जहां भी कच्चा हिस्सा होगा, वहां पेड़-पौधे लगाए जाएंगे। मैं बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष के अंत तक एक भी फुटपाथ या सेंट्रल वर्ज टूटा हुआ नहीं बचेगा। इसके अलावा, अगर सेंट्रल वर्ज या फुटपाथ पर एक फीट भी कच्ची जमीन है, तो उस पर भी पेड़-पौधे लगाकर उसे कवर किया जाएगा। इतना ही नहीं, फुटपाथों की नियमित सफाई, सड़कों के किनारे और डिवाइडर पर लगाए गए पौधों की नियमित धुलाई और समय-समय पर धुलाई के साथ-साथ फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज पर कर्बस्टोन की पेंटिंग भी की जाएगी। इन ढांचों को सुंदर बनाए रखने के लिए हर तीन महीने में इसके रंग रोगन की व्यापक योजना तैयार की गई है।

38. तीसरा- PWD की सड़कों पर धूल जमा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सड़कों पर नियमित अंतराल पर मशीनों द्वारा सड़कों की सफाई और आधुनिक मशीनों द्वारा सड़कों की धुलाई की जाएगी। इसे हासिल करने के लिए, हम 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन और 210 वाटर-स्प्रिंकलर कम एंटी-स्मॉग गन मशीन खरीदेंगे, जिन्हें PWD सड़कों के पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए आवंटित किया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक PWD की सड़कों के एक-एक कोने की सफाई की जाए और वाहनों की आवाजाही से धूल न जमी हो और न ही उड़ रही हो। यही समस्या MCD के अंतर्गत आने वाली सड़कों पर भी मौजूद है। दिल्ली में सभी सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए, दिल्ली सरकार एंटी-स्मॉग गन के साथ एकीकृत 250 वाटर स्प्रिंकलर मशीनों को तैनात करेगी, जिनका शहर की वायु गुणवत्ता में समग्र सुधार के लिए आवश्यकता के आधार पर उपयोग किया जाएगा। सरकार की यह योजना दिल्ली के वायु प्रदूषण में सड़क की धूल के योगदान (जो pm 10 के लिए 35 प्रतिशत व pm 2.5 के लिए 28 प्रतिशत तक हो जाता है) को भी काफ़ी हद तक कम करने में मदद करेगी।

39. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की सड़कों के अपग्रेडेशन और सौंदर्यकरण की यह परियोजना 10 साल की है। इस पर लगभग 19,466 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मैं इस योजना के लिए 2034 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूं।

40. मौजूदा सड़कों के अपग्रेडेशन और सौंदर्यकरण के अलावा, हमारी सरकार 26 नए फ्लाईओवर/ अंडरपास/ पुल परियोजनाओं पर भी जोर देगी जो अभी पाइपलाइन में हैं। इनमें से 10 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, 11 परियोजनाएं डिजाइन अप्रूवल के लिए UTTIPEC को भेजी गई हैं और 5 परियोजनाएं टेंडरिंग की प्रक्रिया में हैं। इनमें कुछ ऐतिहासिक परियोजनाएं शामिल हैं, जैसे कि सराय काले खां से मयूर विहार तक बारापुला फेज-3 फ्लाईओवर, पंजाबी बाग और राजा गार्डन तक फ्लाईओवर और मौजूदा नजफगढ़ फिरनी में एलिवेटेड रोड। पूरा होने पर, ये फ्लाईओवर राष्ट्रीय राजधानी में लाखों निवासियों और पर्यटकों के दैनिक आवागमन के समय को काफी हद तक कम कर देंगे, साथ ही यातायात की भीड़ और वाहन प्रदूषण को भी कम करेंगे। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब दूसरे राज्यों में फ्लाईओवर का निर्माण होता है, तो निर्माण कार्य शुरू होने से लेकर उसके पूरा होने तक निर्माण लागत कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन दिल्ली देश का एकमात्र राज्य है जहां फ्लाईओवर के निर्माण की लागत में वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि ईमानदारी और कुशलता से काम करके सरकार ने जनता के 536 करोड़ रुपये बचाए हैं।

मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में नई फ्लाईओवर परियोजनाओं के लिए 722 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूं।

41. हमारी सरकार DMRC के सहयोग से दिल्ली में 3 अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर बना रही है। ये तीनों फ्लाईओवर भजनपुरा से यमुना विहार, आजादपुर से रानी झांसी चौराहा और साकेत से पुल प्रह्लादपुर तक बनेंगे। डबल डेकर फ्लाईओवर के निचले डेक पर वाहन चलेंगे, जबकि अपर डेक पर मेट्रो चलेगी। इन फ्लाईओवरों को इस तरह डिजाइन

किया गया है कि इसके निर्माण में जनता के 121 करोड़ रुपये बचेंगे। मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन तीनों फ्लाईओवरों के लिए 320 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूं।

42. मैं सड़कों और पुलों की उपरोक्त सभी परियोजनाओं के लिए 3,126 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव करता हूं।

43. अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रगतिशील और आधुनिक शहर की पहचान विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से होती है। बोगोटा के पूर्व मेयर और सस्टेनेबल शहरी विकास के क्षेत्र के जाने-माने विचारक गुस्तावो पेट्रो ने कहा भी है-

'विकसित देश वह नहीं, जहां गरीबों के पास कार हो, बल्कि वह है, जहां अमीर भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हों।'

पेट्रो का यह कथन माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता के तहत पिछले आठ वर्षों में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में किए गए कार्यों के संबंध में बहुत मायने रखता है। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें सभी बड़े शहरों की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को इस हद तक आधुनिक बनाना होगा कि अमीर लोग भी इनका उपयोग करने में सहज और गौरवान्वित महसूस करें।

44. मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले 8 वर्षों में हमने दिल्ली की पूरी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाया है। वर्तमान में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के बेड़े में 7,379 बसें हैं। दिल्ली के इतिहास में यह अब तक की सर्वाधिक संख्या है। ये बसें 600 से अधिक मार्गों पर चल रही हैं। इनमें 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं, जिनकी संख्या वर्ष 2023 के अंत तक 1900 (1800 बसें 12 मीटर लंबी और 100 बसें 9 मीटर लंबी) हो जाएगी। इससे कार्बन डाईऑक्साइड (CO2) के उत्सर्जन में लगभग 1 लाख 7 हजार टन की कमी आएगी। वर्ष 2023 के अंत तक सभी राज्यों की तुलना में दिल्ली के पास इलेक्ट्रिक बसों का सबसे बड़ा बेड़ा होगा।

45. वर्ष 2025 के अंत तक दिल्ली में 10 हजार 480 बसों का बेड़ा होगा। हमारा विजन सिर्फ बसों की संख्या बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यात्रा को प्रदूषण मुक्त बनाना भी है। इसलिए 2025 तक दिल्ली के बेड़े में 80 प्रतिशत (8,280 बसें) इलेक्ट्रिक बसें होंगी और दिल्ली दुनिया के बड़े शहरों की कतार में शामिल हो जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि दिल्ली में हर साल लगभग 4 लाख 60 हजार टन कार्बन डाईऑक्साइड (CO2) का उत्सर्जन कम होगा। इससे दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी।

46. अध्यक्ष महोदय, अक्सर यह शिकायत की जाती है कि दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में शामिल मेट्रो और बस दोनों की सबसे बड़ी समस्या लास्ट-माइल कनेक्टिविटी है। घर या ऑफ़िस के लिए सस्ता व सुविधाजनक फर्स्ट या लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होने के चलते निजी वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने Scientific Route Rationalisation study करवाई और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी मार्गों का एक व्यापक सेट तैयार किया है। यह दिल्ली के मेट्रो और बस नेटवर्क के सभी प्रमुख केंद्रों को एक साथ जोड़ेगा। मुझे यह घोषणा करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली के इतिहास में पहली बार लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने लिए एक समर्पित 'मोहल्ला बस योजना' आगामी वित्तीय वर्ष में शुरू की जाएगी। इन मार्गों पर केवल 9 मीटर लंबाई की प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इन बसों में किराया कलेक्शन मैकेनिज्म को "कॉमन मोबिलिटी कार्ड" यानि "वन दिल्ली कार्ड" के माध्यम से बाकी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के साथ जोड़ा जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष में 100 इलेक्ट्रिक 'मोहल्ला बसें' शुरू होंगी, जिनकी संख्या अगले 3 वर्षों में बढ़कर 2180 हो जाएंगी। इससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी।

47. अगले 12 वर्षों में दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों के मद में 28,556 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। मैं आगामी वित्तीय वर्ष के लिए दिल्ली सरकार की बस सेवाओं के लिए 3,500 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव करता हूं।

48. महोदय, हमारा उद्देश्य केवल दिल्ली के बस बेड़े को बढ़ाना ही नहीं, बल्कि सभी सुविधाओं के साथ यात्रियों की सेफ्टी और सिक्युरिटी के वैश्विक मानकों के अनुरूप पूरी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना भी है। महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी सभी नई बसें फैक्ट्री फिटेड जीपीएस, 3 CCTV कैमरे और 10 पैनिक बटन की सुविधा से लैस होकर आ रही हैं। ये बसें कश्मीरी गेट स्थित अत्याधुनिक सेंट्रलाइज्ड कमांड और कंट्रोल सेंटर के साथ रीयल टाइम में संचालित होती हैं। प्रत्येक बस में यात्रियों की सुरक्षा के लिए मार्शल भी तैनात किया गया है।

49. अध्यक्ष महोदय, जैसा की मैंने पहले कहा, हमारा लक्ष्य दिल्ली की 80 प्रतिशत बसों को 2025 तक इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित करना है। इसीलिए इलेक्ट्रिक बसों के आने से पहले सभी डिपो का विद्युतीकरण जरूरी है। इसमें अपस्ट्रीम Electricity grid का अपग्रेडेशन, हाई टेंशन पावर लाईन बिछाना और हर बस डिपो पर सब-स्टेशन स्थापित करना शामिल है। इस दिशा में सभी 57 बस डिपो में युद्धस्तर पर काम शुरू हो चुका है। इनमें से 3 डिपो का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है, 17 का जून 2023 तक पूरा हो जाएगा और दिसंबर 2023 तक सभी 57 डिपो का विद्युतीकरण हो जाएगा।

दिल्ली सरकार इस पूरी परियोजना पर 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

50. अध्यक्ष महोदय, किसी भी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उद्देश्य यात्रियों की सेवा करना है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाने के लिए सभी वर्गों के यात्रियों के अनुभवों को महत्व देना आवश्यक है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आगामी वित्तीय वर्ष में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन का बुनियादी ढाँचा विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ आधुनिक बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस संबंध में दिल्ली सरकार की प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार हैं-

पहला: - 3 विश्वस्तरीय ISBTs का विकास किया जाएगा। आनंद विहार और सराय काले खां स्थित ISBT, बस नेटवर्क, RRTS और पास के रेलवे स्टेशन का उपयोग

प्रतिदिन लाखों लोग करते हैं। दिल्ली सरकार ने PPP मॉडल के माध्यम से इन दोनों ISBT के पुनर्विकास के लिए DMRC के साथ साझेदारी की है, जिनमें हवाई अड्डों की तर्ज पर सुविधाएं होंगी। इसलिए इन पुनर्विकसित ISBTs को 'बस पोर्ट्स' भी कहा जा सकता है। यात्रियों को कई सुविधाएं प्रदान करने के अलावा, इन बस पोर्ट्स में वाणिज्यिक परिसर भी होंगे, जो रोजगार पैदा करने में भी मदद करेंगे।

द्वारका में भी इसी तर्ज पर एक नया विश्वस्तरीय ISBT बनेगा।

दूसरा:- दिल्ली में जल्द ही हरिनगर और वसंत विहार में दो अनूठे बहुमंजिले बस डिपो बनाए जाएंगे। NBCC के साथ साझेदारी में विकसित ये भारत के पहले बहुमंज़िला बस डिपो होंगे, जिनमें 6 मंज़िल तक बसें खड़ी की जा सकेंगी। बस पार्किंग की क्षमता बढ़ाने के अलावा इन बहुमंज़िला डिपो में शानदार वाणिज्यिक परिसर भी बनेंगे। इससे दिल्ली की आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

तीसरा- घरेलू बस यात्रियों की संतुष्टि और सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने नेहरू प्लेस और नजफगढ़ में DMRC के सहयोग से सभी सुविधाओं से परिपूर्ण दो आधुनिक बस टर्मिनल बनाने का निर्णय लिया गया है। आने वाले वर्षों में शेष बस टर्मिनलों को भी जल्द ही आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्निर्मित किया जाएगा।

चौथा- दिल्ली में 9 नए बस डिपो का निर्माण जोरों पर है, जिसे अगले साल तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे दिल्ली में चलने वाली बसों की क्षमता में काफी विस्तार होगा।

51. अध्यक्ष महोदय, परिवहन व्यवस्था में इन ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ ही हम पूरी दिल्ली में 1400 नए और आधुनिक बस क्यू शेल्टर (BQS) भी बनवाने जा रहे है। इनमें बस यात्रियों के लिए आरामदायक शेल्टर के साथ-साथ रूट मैप व बसों के आगमन

समय को दर्शाती हुई डिजिटल स्क्रीन भी होंगी। G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनज़र दिल्ली सरकार यह कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी।

52. दिल्ली की लाइफ लाइन यमुना जी का गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। इसलिए, दिल्ली को एक 'साफ, सुंदर और आधुनिक शहर' के रूप में विकसित करने के किसी भी प्रयास में यमुना की सफाई और जीर्णोद्धार को सबसे आगे रखा जाना चाहिए। पिछले 8 वर्षों में शुरू किए गए कई प्रयासों के आधार पर दिल्ली सरकार यमुना को साफ करने के लिए छह सूत्रीय कार्ययोजना पर काम कर रही है। इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं-

पहलाः नए एसटीपी/डीएसटीपी का निर्माण और मौजूदा एसटीपी का अपग्रेडेशन- सरकार का लक्ष्य वर्ष 2023-24 में सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता को 258 MGD बढ़ाना है। परिणामस्वरूप, मार्च 2024 तक दिल्ली जल बोर्ड की कुल सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 632 MGD से बढ़ाकर 890 MGD कर दी जाएगी। यह एक वर्ष में 41 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि होगी।

दूसराः शत प्रतिशत घरों तक सीवर कनेक्टिविटी- मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत दिल्ली सरकार अनधिकृत कालोनियों को मुफ्त घरेलू सीवर कनेक्शन प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक घर को सीवर कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए अगले वर्ष 570 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इन सभी कॉलोनियों में घर-घर सीवर कनेक्शन निःशुल्क दिए जाएंगे। इस वित्तीय वर्ष में सीवर कनेक्टिविटी वाली कुल कॉलोनियों की संख्या 747 से बढ़कर 1317 (41 से बढ़कर 73 प्रतिशत तक) हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि 2014 तक दिल्ली में केवल 227 कॉलोनियां (मात्र 13 प्रतिशत) सीवर नेटवर्क से जुड़ी थीं।

तीसराः सीवर नेटवर्क की डिसिल्टिंग- इसके तहत 90km ट्रंक और पेरिफेरल सीवर लाइनों की डिसिल्टिंग की जाएगी।

चौथाः नालों को ट्रैप और डायवर्ट करना- इसके तहत झुग्गी-झोपड़ियों से नालों को ट्रैप एवं डायवर्ट कर मुख्य सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

पांचवां: प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को कंफर्मिंग एरिया में शिफ्ट किया जाएगा।

छठाः यमुना नदी में प्रदूषण कम करने के लिए Major Drains की ट्रैपिंगः Najafgarh Drain, Supplimentary Drain और Shahadara Drain के साथ-साथ इनसे जुड़े छोटे नालों को भी ट्रैप किया जा रहा है। यमुना नदी में गिरने वाले अन्य प्रमुख नालों को भी ट्रैप किया जा रहा है।

53. यमुना को साफ करने के लिए छह सूत्रीय कार्ययोजना के चलते दिल्ली में ट्रीटेड सीवेज की मात्रा 2015 में 373 MGD से बढ़कर मार्च 2024 तक लगभग 890 MGD हो जाएगी। यह आठ वर्षों में लगभग 250 प्रतिशत की वृद्धि है।

54. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को एक 'साफ़, सुंदर और आधुनिक शहर' बनाने की हमारी योजना के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक दिल्ली में कूड़े के तीन पहाड़ों से संबंधित है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूर्व के तीनों नगर निगम (दक्षिण, पूर्व और उत्तरी) को स्वच्छ भारत रैंकिंग में लगातार निचले 10 स्थानों में जगह मिली। इसका बड़ा कारण कूड़े के तीन विशाल पहाड़ थे। हालांकि कुछ वर्षों से इन पहाड़ों को साफ करने के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अनुमान हैं कि मौजूदा गति से इन्हें साफ करने में 197 साल लग जाएंगे। यह अस्वीकार्य है।

55. माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से दिल्ली सरकार ने कूड़े के इन पहाड़ों को साफ करने के लिए MCD के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। हम MCD के साथ मिलकर दो साल के भीतर कूड़े के तीनों पहाड़ों का अंत सुनिश्चित करेंगे। दिसंबर 2023 तक ओखला लैंडफिल, मार्च 2024 तक भलस्वा लैंडफिल और दिसंबर 2024 तक गाजीपुर लैंडफिल को पूरी तरह साफ कर देंगे। दिल्ली को साफ, सुंदर और आधुनिक

दिल्ली बनाने में मदद करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में MCD को 850 करोड़ रुपए के ऋण का प्रस्ताव करता हूं।

महोदय कूड़े के ये तीनों पहाड़ हटाना एमसीडी के लिए कभी बेशक कठिन काम रहा हो, लेकिन हम इसके लिए संकल्प बद्ध हैं और इसका नतीजा दिखने भी लगा है। इस मौके पर एक शेर उपयुक्त लग रहा है कि-

जो कामयाबी हासिल करने का जुनून रखते हैं,

वो समंदर पर भी पत्थर का पुल बना देते हैं।

56. महोदय, मुझे विश्वास है कि दिल्ली को साफ, सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए उपरोक्त योजना अब तक का सबसे व्यापक और महत्वाकांक्षी प्रयास है। यह पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। साथ ही बड़े शहरों के लिए संभावनाओं और आशा की नई किरण है।

सेक्टोरल बजट

शिक्षा

57. अध्यक्ष महोदय, मैं अब शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ प्रमुख प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हर व्यक्ति, हर परिवार, हर राज्य, हर देश खुशहाल बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। दुनिया भर में सरकारें अपने नागरिकों को समृद्ध बनाने के लिए नई पहल, नवाचार के साथ-साथ शांति प्रयासों का भी सहारा ले रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा को हर इंसान की खुशहाली का माध्यम माना है। उन्होंने बार-बार यह संदेश दिया है कि परिवार और बच्चों की खुशहाली का एक मात्र जरिया शिक्षा ही है। अब दिल्ली में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है।

दिल्ली सरकार सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले 8 वर्षों में हमने जो भी वादा किया है, उसे पूरा किया।

58. अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा मॉडल अब सिर्फ सरकारी स्कूल की अच्छी बिल्डिंग बनाने और परीक्षा में अच्छे परिणाम लाने से कहीं आगे निकल चुका है। दिल्ली सरकार ने हर साल शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया है। हमारे स्कूलों में उत्कृष्ट सुविधाएं हैं और हमने शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मानक भी पेश किए हैं। आज हर भारतीय के लिए यह गर्व की बात है कि दुनिया भर में जब भी सरकारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था में उत्कृष्टता की बात होती है तो सबसे पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का उदाहरण दिया जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा जाना माना अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्र अपने पहले पन्ने पर भारत के बेहतरीन शिक्षा मंत्री की तस्वीर के साथ दिल्ली सरकार के स्कूलों की सफलताओं को प्रकाशित करेगा।

59. अध्यक्ष महोदय, न केवल दिल्ली, बल्कि भारत और संभवतः पूरी दुनिया के लिए 2022-23 का यह शैक्षणिक सत्र पहला सामान्य शैक्षणिक सत्र रहा है, जो कोविड-19 महामारी की भयावहता के बाद से बिना किसी बाधा के आगे बढ़ा है। दुनिया की कोई भी सरकार और शिक्षा व्यवस्था कोविड के असर से बच नहीं पाई है। मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि 2020 से पहले केजरीवाल सरकार ने जो कदम उठाए, उससे हमें वह आधार मिला, जिससे हम इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने बच्चों की पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव कम हुआ ।

60. संक्षेप में हम कह सकते हैं कि तकनीक की मदद से, मेडिटेशन के माइंडफुलनेस अभ्यास और माता-पिता और शिक्षकों के सहयोग से, हमारे बच्चों ने न केवल तनाव पर नियंत्रण रखा बल्कि पूरे कोरोना काल में शिक्षा से भी जुड़े रहे। उन्होंने बोर्ड परीक्षा, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया। अध्यक्ष महोदय,

इन प्रयासों का नतीजा यह है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने 12वीं कक्षा में 98 प्रतिशत परिणाम प्राप्त किए हैं। इसके अलावा JEE MAINS में 493 और NEET में 648 बच्चे कामयाब हुए हैं।

61. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि Entrepreneurship mindset curriculum के 12वीं कक्षा के छात्रों के पहले बैच में से 56 छात्रों ने Business Blasters पहल के माध्यम से उद्यमशीलता में अपनी योग्यता साबित की और दिल्ली सरकार के शीर्ष 7 विश्वविद्यालयों में BBA और B.TECH जैसे पाठ्यक्रमों में सीधे दाखिला पाया । मुझे विश्वास है कि ये बच्चे न केवल अपने लिए नई दिशा तय करेंगे बल्कि इस प्रयोग से देश की उच्च शिक्षा को भी नया आयाम मिलेगा।

62. इसी तरह 2021 से लागू देशभक्ति पाठ्यक्रम भी हमारे बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि वे हर भारतीय को जाति और धर्म के चश्मे से नहीं, बल्कि मानवता के नजरिए से देखें। यह पाठ्यक्रम हमारे बच्चों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही मायने में समझने और निभाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहा है।

63. वर्ष 2022-23 दिल्ली की शिक्षा के लिए और भी कई मायनों में उल्लेखनीय रहा है। शहीद-ए-आजम भगत सिंह को समर्पित दिल्ली के पहले आवासीय Armed Forces Preparatory School का उद्‌घाटन नजफगढ़ के झाडौदा कलां गांव में हुआ । वर्तमान में इस स्कूल में 160 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो जल्द ही armed forces में शामिल होकर मातृभूमि की सेवा करेंगे। इसके अलावा Delhi Model Virtual School भी एक सफल प्रयोग के तौर पर सामने आया है। सच्चे अर्थों में यह देश का पहला वर्चुअल स्कूल है। इसके पहले बैच में गोवा, कर्नाटक, ओडिशा, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित 14 राज्यों के छात्र शामिल हैं।

64. अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों और principals का प्रशिक्षण केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल का अभिन्न अंग है। हमने इस वर्ष 98 principals को प्रशिक्षण के लिए IIM

अहमदाबाद भेजा है, जबकि हमारे 56 principal और शिक्षक-प्रशिक्षक leadership training के लिए Cambridge गए थे। यदि राजनीतिक संकीर्णता आड़े नहीं आती तो 60 प्राथमिक शिक्षकों को भी Early Childhood and primary schooling में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजा गया होता। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में फिनलैंड, सिंगापुर और Cambridge में 1410 principals, शिक्षकों और शिक्षक-प्रशिक्षकों ने विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है। हमारे देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों और principals का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शायद ही कराया हो। अब तक हमारे 1247 principals ने IIM अहमदाबाद से और 61 principals ने IIM लखनऊ से प्रशिक्षण लिया है। इस विषय में मैं यह भी बताना चाहूंगा कि विदेशों के साथ-साथ हमने अपने शिक्षकों को शिक्षा के नए मॉडल का अध्ययन करने और समझने के लिए त्रिपुरा से गुजरात और कश्मीर से तमिलनाडु तक विभिन्न राज्यों में भी भेजा है।

65. अध्यक्ष महोदय, 2015 में केजरीवाल सरकार बनने के बाद से अब तक हमने सीधी भर्ती के माध्यम से 24,144 शिक्षकों की नियुक्ति की है। इतने कम समय में इतना बड़ा भर्ती अभियान किसी भी राज्य में पहले कभी नहीं हुआ। .

66. अध्यक्ष महोदय, हम वित्तीय वर्ष 2023-24 में शिक्षा में उत्कृष्टता और नवाचार की इसी भावना को कई नई योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जारी रखेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, वर्ष 2018 में सभी शिक्षकों को टेबलेट देना एक दूरदर्शी कदम था। इस कदम के महत्व को महसूस करते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि पिछले टैबलेट अब चार साल से अधिक पुराने हैं इसलिए हम अपने सभी शिक्षकों (नियमित, अतिथि और अनुबंधात्मक सहित), वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और DDEs को नए टैबलेट प्रदान करेंगे।

इसके साथ ही हम चरणबद्ध तरीके से हर स्कूल में कम से कम 20 नए कंप्यूटर भी उपलब्ध कराएंगे ताकि इन उपकरणों की मदद से नई अवधारणाओं को शिक्षा में शामिल किया जा सके और साथ ही शैक्षिक मूल्यांकन में भी इजाफा किया जा सके। वर्ष 2023-24 में हम इन उपकरणों को 350 स्कूलों में उपलब्ध कराएंगे।

67. Dr. Ambedkar Schools of Specialized Excellence (SoSE) की शुरुआत 2021 में 20 स्कूलों के साथ हुई थी। हम आने वाले साल में इसे बढ़ाकर 37 कर देंगे। अब इनमें करीब 10 हजार बच्चे पढ़ सकेंगे। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली का प्रत्येक बच्चा, जिसके पास विशिष्ट प्रतिभा है, वह अपने घर के निकटतम किसी SoSE में प्रवेश पाने में सक्षम हो। ये सभी स्कूल दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से affiliate होंगे।

68. SoSE में विशेषज्ञताओं को वैश्विक परिवेश को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई है। इसलिए हम इन स्कूलों में बच्चों को फ्रेंच, जर्मन, जैपनीज और स्पेनिश भाषाएँ भी पढ़ा रहे हैं। इनके साथ इस पायलट प्रोजेक्ट से मिली सीख के आधार पर हम आने वाले वर्षों में इसे सभी स्कूलों में लागू करने पर विचार करेंगे।

69. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि SoSE के तहत STEM - यानी साइंस, टैकनोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित में विशेषज्ञता के पहले बैच के 676 बच्चे दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें से 253 विद्यार्थियों ने JEE MAINS की परीक्षा दी और लगभग 50 प्रतिशत यानी 114 ने JEE Advance के लिए क्वालीफाई किया है।

70. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि देश में पहली बार स्कूल और उद्योग मिलकर काम करेंगे। केजरीवाल सरकार ने हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए 12 नए School of Applied Learning शुरू किए हैं। इन स्कूलों में न केवल पारंपरिक विषय होंगे बल्कि छात्रों को अपना कौशल विकसित करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए एक पेशेवर औद्योगिक सेटअप भी होगा। ये स्कूल

दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होंगे। इन स्कूलों में कक्षा 9वीं से उच्च गुणवत्ता वाले कौशल विषय भी अनिवार्य रूप से शुरू किए जाएंगे। हर बच्चा कक्षा 9वीं और 10वीं में तीन-तीन कौशल विषय और कक्षा 11वीं और 12वीं में एक-एक कौशल विषय का अध्ययन करेगा। इस पहल का उद्देश्य यह है कि हर बच्चे को पारंपरिक विषयों के साथ-साथ ऐसे कौशल भी सीखने चाहिए जो उसे नए जमाने की चुनौतियों के लिए तैयार करें। हमारा मानना है कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार के School of Applied Learning ज्ञान, कौशल और ऐटिटूड के साथ समग्र शिक्षा का नया मॉडल प्रस्तुत करेंगे ।

71. महोदय, हम सभी जानते हैं कि MCD के स्कूल दिल्ली सरकार के फीडर स्कूल हैं। इन स्कूलों के लगभग 1 लाख 80 हज़ार बच्चे हर साल दिल्ली सरकार के स्कूलों में छठी कक्षा में प्रवेश लेते हैं। 2016 में हमने पाया कि छठी कक्षा के 76 प्रतिशत बच्चे अपनी किताबें भी नहीं पढ़ सकते थे। दिल्ली सरकार के 'चुनौती' और 'मिशन बुनियाद' कार्यक्रमों के माध्यम से हम बच्चों के पढ़ने, लिखने और गणित की बुनियादी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं । यह सिलसिला हर साल चलता है। इसलिए, इस वर्ष से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सुझाए गए "स्कूल काम्प्लेक्स" पर काम करेंगे। दिल्ली सरकार के स्कूल अपने सभी फीडर स्कूलों और क्षेत्र की आंगनवाड़ियों को साथ लेकर चलेंगे ताकि सभी बच्चों का मूलभूत कौशल विकसित हो सके ।ताकि जब बच्चा छठी कक्षा में दिल्ली के सरकारी स्कूल में दाखिल हो, तो उसकी सीखने की क्षमता उसकी क्लास के अनुसार हो।

72. दिल्ली सरकार ने पिछले पांच वर्षों में कई अत्याधुनिक खेल परिसर विकसित किए हैं। इनमे कैर (नजफगढ़) में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर, मुंढेला खेल परिसर और पहलादपुर खेल परिसर शामिल हैं। कुछ प्रस्तावित परियोजनाओं में एक कुश्ती छात्रावास और छत्रसाल स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक की relaying, राजीव गांधी स्टेडियम का अपग्रेडेशन और त्यागराज स्टेडियम में Squash सेंटर का निर्माण शामिल है। भविष्य में सरकार नजफगढ़ के समसपुर खालसा में एक Multipurpose Sports Complex विकसित करने की

योजना बना रही है। इसके लिए 35 एकड़ भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। पिछले 8 वर्षों में सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 9,000 से अधिक खिलाड़ियों को 110 करोड़ की राशि वितरित की है।

73. महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 16 हज़ार 575 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव करता हूं।

पर्यावरण और वन

74. अध्यक्ष महोदय, अथर्ववेद में "माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः" का उल्लेख है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए हैं कि हम दिल्ली की प्रकृति और पर्यावरण के साथ वैसा ही व्यवहार करें, जैसा हम अपनी मां के साथ करते हैं। वैसा ही स्नेह और देखभाल करें ताकि वे अनंतकाल तक हमारे साथ रहे।

75. मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता की मेहनत की बदौलत पिछले 8 साल में किए गए प्रयासों के शानदार परिणाम दिखने लगे हैं। दिल्ली की हवा में पीएम-10 की मौजूदगी साल 2014 में 324 पीपीएम थी, जो 2022 में घटकर 223 पीपीएम रह गई है। इसी तरह दिल्ली की हवा में पीएम-2.5 की मौजूदगी 2014 में 149 पीपीएम थी, जो 2022 में कम होकर 103 पीपीएम हो गई है। पिछले 8 वर्षों में पीएम-10 और पीएम-2.5 दोनों की मात्रा में 30% से अधिक की कमी आई है। इन आंकड़ों से साफ है कि 2014 के मुकाबले दिल्ली की हवा में प्रदूषण 30 फीसदी कम हुआ है।

76. पिछले कुछ वर्षों में "गंभीर" वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या में भी भारी कमी आई है। 2016 में यह 26 दिन थे जो कि 2022 में घटकर मात्र 6 दिन रह गए । इस अवधि के दौरान “अच्छी” से “मध्यम” वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

यह 109 से बढ़कर 163 दिन हो गए हैं। स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता के प्रयासों से बेहतर वायु गुणवाता के दिनों की संख्या अब बढ़ने लगी है ।

77. दिल्ली सरकार द्वारा युद्धस्तर पर फारेस्ट कवर बढ़ाने के अभियान का प्रदूषण कम करने में बड़ा योगदान रहा है। आज दिल्ली में प्रति व्यक्ति फारेस्ट कवर 11.6 वर्ग मीटर है, जो देश के अन्य सभी महानगरों से अधिक है। दिल्ली की तुलना में हैदराबाद का प्रति व्यक्ति फारेस्ट कवर 10.6 , बेंगलुरु 10.4 , मुंबई 6.0, चेन्नई 2.6 और कोलकाता 0.1 वर्ग मीटर है।

78. अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली ने जो प्रगति की है, वह अचानक रातों-रात नहीं हुई है। यह सरकार के निरंतर, एकाग्र और कड़ी मेहनत का परिणाम है। पिछले साल सरकार ने 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्ययोजना तैयार की थी। इसके तहत धूल, कचरा जलाने और अन्य प्रदूषण हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने वाली 27 एजेंसियों/विभागों के कार्यों में समन्वय के लिए एक ग्रीन वॉर रूम बनाया गया था। सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सर्दियों के महीनों के दौरान 84 मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन, 609 स्प्रिंकलर और 639 एंटी-स्मॉग गन भी तैनात किए। ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से नागरिकों द्वारा की गई सभी शिकायतों में से 90% से अधिक का समाधान किया गया। हमारी सरकार ने प्रदूषण के विभिन्न कारणों की वास्तविक समय पर पहचान करने के लिए एक आधुनिक लैब की स्थापना की। इससे वायु प्रदूषण से संबंधित डेटा को मजबूत करने के लिए एक नया बेंचमार्क बना। IIT कानपुर, IIT दिल्ली और TERI के सहयोग से स्थापित लैब से सरकार को प्रदूषण के सही समय और कारणों की जानकारी मिलनी शुरू हो गई है।

79. अध्यक्ष महोदय, हमें अभी भी प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक लंबा रास्ता तय करना है। इसे ध्यान में रखते हुए उपरोक्त उपायों को जारी रखने के साथ-साथ मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले नए कदमों की घोषणा करना चाहूंगा।

80. हम पूरी दिल्ली में 11 मोबाइल वैन (प्रत्येक जिले में एक) तैनात करके प्रदूषण की real time source apportionment परियोजना को अगले स्तर तक ले जाएंगे।

81. सड़क की धूल को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने सभी 1400 किलोमीटर लंबी PWD सड़कों को साफ रखने, फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज टूटा नहीं छोड़ने और खाली कच्चे हिस्सों में घास, झाड़ियां और पेड़ लगाने का फैसला किया है। सरकार ने पेड़ लगाने, सड़कों पर पानी छिड़कने और सड़कों को आधुनिक मशीनों से नियमित रूप से धोने की एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं।

82. सरकार 52 लाख पेड़ लगाकर अगले साल वृक्षारोपण के अपने महाअभियान को तेज करेगी। हम दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नगर-वनों को बेहतर बनाने की नीतियों पर भी काम करना जारी रखेंगे, ताकि ये वन हमारे नागरिकों के सामान्य जीवन का हिस्सा बन सकें और पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकें।

83. मुझे यकीन है कि इन प्रयासों से दिल्ली न केवल वन क्षेत्र का संरक्षण करेगी, बल्कि शहर में पेड़ों की संख्या भी बढ़ाएगी। प्रत्येक नया पेड़ आने वाले वर्षों में दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ हवा में सांस लेने में मदद करेगा।

स्वास्थ्य

84. अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी दिल्ली मॉडल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। पिछले आठ वर्षों में, दिल्ली के लोगों को स्वस्थ रखना और उनकी छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारियों तक उनका ध्यान रखना दिल्ली सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य के केंद्र बिंदु में रहा है।

85. सभी को याद होगा कि 2015 से पहले दिल्ली में प्राइमरी हेल्थ के नाम पर केवल डिस्पेंसरियां होती थीं, जिनमें न डॉक्टर होते थे और न ही दवाइयां होती थीं। आज, 2023 में, मैं आपको इस तथ्य की एक झलक पेश करना चाहता हूं कि कैसे दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार के पास आज 515 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक, 4 महिला मोहल्ला क्लीनिक, 175 एलोपैथिक डिस्पेंसरी, 60 प्राइमरी अर्बन हेल्थ सेंटर, 30 पॉलीक्लिनिक और 39 मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मौजूद हैं, जिसमें 14,244 बेड उपलब्ध हैं, जहां हर साल 4 करोड़ से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

86. आज हमारे मोहल्ला क्लीनिक दिल्ली के प्राइमरी हेल्थ केयर की रीढ़ बन गए हैं, जहां MBBS डॉक्टर पूरे सेवा भाव से लोगों का इलाज करते हैं। यहां 250 से अधिक डायग्नोस्टिक टेस्ट और 165 आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसका फायदा यह है कि इन मोहल्ला क्लीनिकों में सालाना करीब 2 करोड़ लोग इलाज के लिए आ रहे हैं। पिछले 8 सालों में हमने एक ऐसा मजबूत हेल्थ केयर मॉडल तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की है जिस पर दिल्ली के लोग भरोसा कर सकें और जहां लोग गर्व के साथ अपना इलाज कराने जा सकें।अध्यक्ष महोदय, हमने मेट्रो स्टेशनों पर मोहल्ला क्लीनिक स्थापित करने की भी योजना बनाई है ताकि दिल्ली के नागरिकों को उनकी जरूरत की स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल सकें।

87. अध्यक्ष महोदय, पिछले साल हमने दिल्ली में महिला मोहल्ला क्लीनिक स्थापित कर महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की एक नई पहल की थी। भारत और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि केवल 37 प्रतिशत महिलाएं ही अपनी सामान्य बीमारियों के लिए ओपीडी में जाती हैं। दिल्ली की जरूरत को और समझने के लिए दिल्ली सरकार ने भी एक सर्वे कराया जिसमें पाया गया कि 51 प्रतिशत महिलाएं बीमारी के लक्षण होने के बावजूद डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। इसके मद्देनजर हमारी सरकार ने पिछले बजट में महिला मोहल्ला क्लीनिक की घोषणा की थी और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि देश में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली में महिला मोहल्ला क्लीनिक की शुरुआत हुई। महिला मोहल्ला क्लिनिक में महिलाओं के लिए कई स्पेशलाइज्ड सुविधाएँ उपलब्ध हैं जिनमें सर्वाइकल कैंसर की जांच और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए टीकाकरण शामिल हैं। अभी दिल्ली में 4 महिला मोहल्ला क्लिनिक का संचालन हो रहा है, जहां पिछले चार महीनों में 42 हज़ार से ज़्यादा महिलाओं ने इलाज कराया है। महिला मोहल्ला क्लीनिक को मिल रहे अच्छे रिस्पॉस को देखते हुए हमने अगले वित्तीय वर्ष दिल्ली में 100 महिला मोहल्ला क्लीनिक खोलने की योजना बनाई है।

88. अध्यक्ष महोदय, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में डायग्नोस्टिक टेस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। किसी बीमारी का सही इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट ठीक से हुआ है या नहीं। सही डायग्नोस्टिक टेस्ट के अभाव में छोटी बीमारी भी गंभीर हो जाती है और उसके बाद उस पर काबू पाना नामुमकिन हो जाता है। दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक की सफलता के तीन बड़े कारक हैं। यहां मुफ्त मेडिकल परामर्श और दवाओं के साथ देश के बेहतरीन लैब से 250 से ज्यादा तरह के टेस्ट भी फ्री होते हैं। दिल्ली सरकार ने अब इसकी संख्या बढाकर 450 करने का निर्णय लिया है।यह मुफ्त सुविधा पॉलीक्लिनिक, डिस्पेंसरी और अस्पतालों में भी

उपलब्ध होगी। इनमें HCV Genotyping, Antibody titre आदि जैसे टेस्ट शामिल हैं। ये टेस्ट सरकारी अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से कराए जाएंगे।

89. माननीय मुख्यमंत्री कुशल नेतृत्वमें दिल्ली सरकार 9 नए सरकारी अस्पतालों का तेजी से निर्माण कर रही है। यह अस्पताल ज्वालापुरी, मादीपुर, शालीमार बाग, हस्तसाल, सिरसपुर, सरिता विहार, रघुवीर नगर, सुल्तानपुरी और किराड़ी में बन रहे हैं। इनमें से चार अस्पताल अगले वित्तीय वर्ष में चालू हो जाएंगे। साथ ही चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, जीटीबी समेत 15 अस्पतालों के नव-निर्माण और विस्तार का काम भी शुरू हो गया है।

इन सभी प्रयासों से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मरीजों के लिए उपलब्ध बेड की संख्या 14,000 से बढ़कर लगभग 30,000 हो जाएगी।

90. दिल्ली में हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (HIMS) और हेल्थ कार्ड जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। HIMS और हेल्थ कार्ड सिस्टम के जरिए दिल्ली के लोग बिना अपना पुराना रिकॉर्ड लिए किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे।

91. 2017 में शुरू हुआ 'दिल्ली आरोग्य कोष' केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत अगर सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन, स्कैनिंग या इम्प्लांट आदि के लिए वेटिंग पीरियड लंबा है तो मरीज सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज करा सकता है, जिसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच वर्षों में, 5 लाख से अधिक लोगों ने केजरीवाल सरकार की इस योजना का लाभ उठाया है।

92. अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में 9,742 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूं।

<u>परिवहन</u>

93. अध्यक्ष महोदय, मैं अब परिवहन विभाग से संबंधित कुछ प्रमुख प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि किसी भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में लास्ट माइल कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में नई **'मोहल्ला बस**' योजना की शुरुआत करने जा रही है। **लास्ट माइल कनेक्टिविटी** के महत्व को ध्यान में रखते हुए पिछले साल परिवहन विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए 4261 LOI जारी किए गए हैं। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने द्वारका में इलेक्ट्रिक स्कूटर शेयरिंग सेवा की भी घोषणा की है। इसके तहत मेट्रो स्टेशनों, बस डिपो, मार्केट्स, मॉल और शिक्षण संस्थानों जैसे अधिक भीड़-भाड़ वाले 250 स्थानों पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 1,500 ई-स्कूटरों को तैनात किया जाएगा। दिल्ली सरकार जल्द ही यह सेवा शुरू करने जा रही है।

94. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली देश का पहला राज्य है, जिसने बसों में महिलाओं की यात्रा को मुफ्त किया। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साढ़े तीन साल में सुरक्षा और सहूलियत के साथ महिलाओं ने दिल्ली की बसों में 100 करोड़ से ज्यादा बार मुफ्त में यात्रा की। मुझे विश्वास है कि इस योजना ने महिलाओं के लिए रोजगार के साथ-साथ शिक्षा के भी नए द्वार खोले हैं। दिल्ली सरकार महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा जारी रखेगी।

95. महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को **डीटीसी बस चालक** के रूप में नियुक्त किया है ताकि उनको आगे लाया जा सके। मुझे यह कहते हुए बेहद गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे पास दिल्ली में डीटीसी बसें चलाने वाली 34 महिला चालक हैं। यह भारत में किसी भी परिवहन निगम में चालकों के रूप में महिलाओं की सर्वाधिक

भागीदारी है। हम यहीं नहीं रूकने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में ऐसे भी बस डिपो होंगे, जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। इनमें ड्राइवर, कंडक्टर, मार्शल समेत पूरा स्टाफ महिलाएं ही होंगी।

96. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का अपना ऑल इन वन पब्लिक मोबिलिटी ऐप 'वन दिल्ली' नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। इस ऐप के द्वारा कोई भी व्यक्ति हमारी तमाम बसों को रियल टाइम में ट्रैक कर सकता है। यह ऐप बस स्टॉप पर आने वाली अगली बस का रियल टाइम बताता है। साथ ही, बसों में कंटैक्टलेस टिकट खरीदने की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके अलावा, यह ऐप दिल्ली में मौजूद 2300 से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों तक पहुंचने में भी मदद करता है। लोग इस ऐप के माध्यम से बसों और ईवी चार्जर के संबंध में अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

97. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली ईवी पॉलिसी अगस्त 2023 में 3 साल पूरे करने जा रही है। यह पॉलिसी दिल्ली में काफी सफल रही है और दिल्ली को EV Capital बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दिल्ली सरकार ने चौतरफा जागरूकता अभियान के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकार ने ईवी खरीदारों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन की पेशकश भी की है और दिल्ली में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क स्थापित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि इस ईवी पॉलिसी की शानदार सफलता का श्रेय सही मायने में दिल्लीवासियों को जाता है, जिन्होंने नई तकनीक होने के बावजूद इलेक्ट्रिक वाहनों को खुले दिल से अपनाया है। ईवी पॉलिसी लॉन्च होने के बाद से दिल्ली में 1 लाख 4 हजार इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए जा चुके हैं। दिसंबर 2022 में दिल्ली में बिकने वाले कुल वाहनों का 16.7 प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों का था। यह देश भर में अब तक की सर्वाधिक संख्या है। ईवी खरीद पर दिल्ली सरकार अब तक 145 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दे चुकी है।

98. इस अवसर पर मैं यह भी घोषणा करना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार जल्द ही ऐप बेस्ड प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम शुरू करेगी। इसके तहत निजी बस ऑपरेटरों को यात्रियों की मांग के अनुसार ऐप बेस्ड प्रीमियम एसी बसें चलाने की अनुमति दी जाएगी। यह निजी वाहन इस्तेमाल करने वालों को सार्वजनिक परिवहन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा और दिल्ली में प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार बहुत जल्द दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम की भी शुरूआत करेगी।

99. **फेसलेस सेवाएं**ः माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीओ) की 45 सेवाओं को फेसलेस कर दिया है। अब दिल्ली के लोग घर बैठे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से संबंधित काम करा सकते हैं। अब उन्हें ट्रांसपोर्ट विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। मुझे इस सम्मानित सदन को सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि दिसंबर 2022 तक 35 लाख 19 हजार फेसलेस आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। इस मामले में भी दिल्ली देश का अग्रणी राज्य है। यह हम सभी दिल्लीवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि अन्य राज्य भी दिल्ली से प्रेरणा लेकर अपने यहां फेसलेस सेवा शुरू कर रहे हैं।

100. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार ने परिवहन सेवाओं में भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने के उद्देश्य से कई नई पहल भी की है। इसके तहत वाहन डीलरों को वाहन खरीदार को शोरूम से ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। मुझे इस सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब तक 8 लाख से अधिक वाहन खरीदारों को शोरूम से ही आरसी जारी की जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्द यह सुविधा कमर्शियल वाहनों के खरीदारों को भी देने की योजना है।

101. अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य के लिए सड़क सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दिल्ली सरकार ने अपने नागरिकों के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाने की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में कई ठोस कदम उठाए हैं। इस दिशा में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक एक पहल थी, जो यह सुनिश्चित करता है कि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से पहले स्किल टेस्ट पास करना ही होगा। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली में सभी 13 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स को ऑटोमेटेड कर दिया गया है। अब दिल्ली में मैनुअल ड्राइविंग टेस्ट नहीं होता है। इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है।

102. मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परिवहन सेक्टर में 9 हज़ार 337 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूं।

श्रम

103. अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में व्यापारियों, व्यवसायियों और दुकानदारों के अलावा लाखों श्रमिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। नए संसद भवन की एक-एक ईंट लगाने से लेकर हमारे लिए पुल, सड़कें, नालियां, पार्क बनाने और विभिन्न संस्थानों में काम करने वाले कामगार दिल्ली के जीवन का अहम और अभिन्न अंग हैं। इसलिए दिल्ली में सत्ता में आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण फैसला किया। मुझे गर्व है कि आज हमारी दिल्ली में श्रमिकों को देश में सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी मिलती है। श्रम विभाग ने अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 16 हजार 792 रुपए प्रति माह, अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए 18 हजार 499 रुपए और कुशल श्रमिकों के लिए 20 हजार 357 रुपए प्रति माह निर्धारित किया है। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी 10

हजार 243 रुपए प्रति माह है और उत्तर प्रदेश में यह मात्र 9 हजार 743 रुपए प्रति माह है।

104. इसका फायदा यह है कि जब एक श्रमिक ज्यादा मेहनताना पाता है तो उसके पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होता है। जब लाखों श्रमिकों के हाथ में खर्च के लिए ज्यादा पैसा होता है तो यह अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाता है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है और आखिरकार इससे अधिक रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

105. दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों को दिल्ली के निर्माणकर्ता और निर्माता के रूप में देखती है और उनके हितों की लगातार रक्षा भी करती है। कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने 'Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board' के तहत लगभग 3 लाख निर्माण श्रमिकों को 258 करोड़ रुपए की राहत राशि 3 किश्तों में 5000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी थी। पिछली सर्दियों में चरम प्रदूषण के दौरान निर्माण गतिविधियां बंद होने के कारण 5 लाख 40 हज़ार श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हुई थी। इस दौरान भी सरकार ने 5000 रुपए प्रति श्रमिक के हिसाब से 270 करोड़ रुपए की राहत दी थी।

106. माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार वर्तमान में निर्माण श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ, शिक्षा लाभ, स्वास्थ्य लाभ, दुर्घटना लाभ, मृत्यु एवं पेंशन लाभ आदि 17 कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इस साल निर्माण श्रमिकों के लिए 4 नई योजनाएं शुरू करने जा रही है-

-कौशल विकासः निर्माण स्थलों पर काम करने वाले सभी पंजीकृत श्रमिकों के लिए ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। विभाग ने इस योजना के माध्यम से 2 लाख निर्माण श्रमिकों को ऑन साइट प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है।

-टूल किट वितरण योजनाः इस योजना के तहत प्रत्येक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में निर्माण श्रमिकों को उसकी आवश्कतानुसार निःशुल्क टूलकिट प्रदान की जाएगी।

-डॉक्टर ऑन व्हील्सः इस योजना के तहत सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को निर्माण स्थल पर मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी।

- निर्माण स्थल पर क्रेचः इस योजना के तहत निर्माण स्थल पर श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त क्रेच की सुविधा प्रदान की जाएगी और साइट पर श्रमिकों के बच्चों को एक समय का पौष्टिक भोजन दिया जाएगा।

राजस्व

107. अध्यक्ष महोदय, हमने दिल्ली के लोगों की आस्थाओं और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। एक बेटे की भूमिका निभाते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' के तहत दिल्ली के करीब 70 हजार बुजुर्गों को देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई है। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार द्वारा अयोध्या, द्वारकाधीश, पुरी, वाराणसी, माँ वैष्णो देवी धाम, अजमेर शरीफ, रामेश्वरम, शिरडी, तिरुपति बालाजी, अमृतसर सहित धार्मिक आस्थाओं के 15 स्थानों पर बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा का सफल आयोजन किया जाता है।

108. दिल्ली में रहने वाले लाखों पूर्वांचलियों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार पिछले 8 सालों से छठ महापर्व धूमधाम से मनाती आ रही है। मैं इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि 2014 में लगभग 100 छठ घाट थे, जो अब 10 गुना होकर लगभग 1100 हो गए हैं। यहां दिल्ली सरकार द्वारा हर संभव व्यवस्था की जाती है ताकि श्रद्धालु, बुनियादी सुविधाओं की चिंता किए बिना अनुष्ठान संपन्न कर सकें। साथ ही, कावड़ियों की सुविधा के लिए हमारी सरकार प्रतिवर्ष दिल्ली में 175 जगहों पर कांवड़ कैंप लगाती है। इसी तरह, दिल्ली के लोगों को उत्तराखंड की

समृद्ध संस्कृति से अवगत कराने और इसे संरक्षित करने के लिए सरकार पूरी दिल्ली में लगभग 100 स्थानों पर 'उत्तरायणी महोत्सव' आयोजित करती है। मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी इन सभी योजनाओं को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं।

109. अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अक्तूबर 2021 और जनवरी 2022 में बेमौसम बारिश और तूफ़ान के कारण दिल्ली में फ़सलों को भारी नुक़सान पहुंचा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों की पीड़ा को समझ कर इस नुक़सान की भरपाई के लिए मुआवज़े की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार ने 20 हज़ार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दो चरणों में 45 करोड़ रुपए की मुआवज़ा राशि वितरित की है। मैं सदन के माध्यम से दिल्ली के किसान भाइयों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि केजरीवाल सरकार हमेशा की तरह आपके कठिन समय में आपके साथ है।

जलापूर्ति

110. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली की जनता के लिए दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर मिशन मोड में काम कर रहा है। पहला है स्वच्छ यमुना परियोजना, जिसका उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूं और दूसरा है- 24 घंटे स्वच्छ जल की आपूर्ति की व्यवस्था करना। देश की राजधानी दिल्ली का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तभी चमकेगा, जब आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं वैश्विक मानकों के अनुरूप होंगी। इसलिए दिल्ली सरकार हर घर में पानी की पाइप लाइन बिछाने, पानी का कनेक्शन देने और 24 घंटे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना पर मिशन मोड में काम कर रहे हैं।

111. इस सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने 1671 अनधिकृत कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन बिछाना सुनिश्चित किया है। यह दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों का लगभग 93 प्रतिशत है। 1671 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1630 में जलापूर्ति भी शुरू की जा चुकी है।

112. मैं यहां बताना चाहूंगा कि 2015 में केवल 985 अनधिकृत कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन थी, जो अब बढ़कर 1671 हो गई है। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली की विभिन्न कॉलोनियों में लगभग 5,138 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का मुश्किल प्रतीत होने वाला कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सुचारू जल आपूर्ति सुनिश्चित करने और विभिन्न कॉलोनियों में समान जल आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए 3000 से अधिक वाटर फ्लो मीटर लगाए गए हैं। वाटर फ्लो मीटर लगाने का यह काम 2015 में शुरू किया गया था, जिससे क्षेत्रवार पानी के वितरण और पानी की बर्बादी का पता लगाना आसान हो गया है।

113. पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आवश्यकता अनुसार जलापूर्ति बढ़ाने के लिए मार्च 2025 तक पानी की उपलब्धता वर्तमान 995 MGD से बढ़ाकर लगभग 1240 MGD करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

114. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के मिशन में दिल्ली सरकार दो स्तरों पर काम कर रही है- पहला भू-जल का स्तर बढ़ाना और दूसरा, बारिश के मौसम में दिल्ली की सड़कों पर बहने वाले पानी का संचयन करना। इस दौरान यमुना में उपलब्ध अतिरिक्त पानी को जमीन के नीचे संरक्षित करना भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 2019 में पल्ला में शुरू की गई बाढ़ जल संचयन की प्रायोगिक परियोजना प्रति वर्ष 800-1000 MG तक भूजल का पुनर्भरण कर रही है। इससे संबंधित क्षेत्रों के भूजल स्तर में करीब 2 मीटर की वृद्धि हुई है। यमुना में बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी को रिचार्ज करने के अलावा, पूरी दिल्ली में बड़े पैमाने पर जल पुनर्भरण परियोजनाएं चल रही हैं। अगले वित्तीय वर्ष में विभिन्न झीलों और अन्य स्रोतों से रोजाना 100 MGD पानी रिचार्ज किया जाएगा।

115. दिल्ली में पानी की आवश्यकता, पीने के साथ-साथ अन्य प्रयोजनों के लिए भी है, जिनमें ग्रीन बेल्ट, फार्महाउस, जल निकाय आदि शामिल हैं। सरकार यह सुनिश्चित कर

रही है कि पेयजल या भूजल का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सरकार की इच्छा है कि एसटीपी से निकलने वाले पानी का उपयोग गैर-पीने योग्य उद्देश्यों के लिए प्रमुखता से किया जाए। इसके लिए सरकार एक बड़ा पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित कर रही है।

116. माननीय मुख्यमंत्री जी के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली को 'झीलों का शहर' बनाने का अभियान भी युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। हमारी सरकार कुछ महीनों में 20 बड़ी झीलों को पुनर्जीवित करने का काम पूरा कर लेगी। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि द्वारका एसटीपी में बनाई गई झीलों ने एक साल की छोटी सी अवधि के भीतर भूजल स्तर में 5.5 मीटर की वृद्धि की है। इन झीलों को जनता के लिए खुले स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे मनोरंजन और पर्यटन के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

117. दिल्ली जल बोर्ड ने अपने राजस्व नेटवर्क में 28 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को शामिल किया है। पिछले वर्ष लगभग 19 लाख व्यक्तिगत उपभोक्ताओं ने प्रति माह 20 हजार लीटर पानी की निःशुल्क आपूर्ति की योजना का लाभ उठाया है।

118. अध्यक्ष महोदय, समाज के सबसे गरीब तबके को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार इस वित्तीय वर्ष में झुग्गी बस्तियों, अनधिकृत कॉलोनियों और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में 1000 आरओ प्लांट लगाने जा रही है। इससे इन इलाकों में रहने वाले लोगों को 24 घंटे साफ पानी मिल सकेगा।

119. मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में जल क्षेत्र के लिए 6 हज़ार 342 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव करता हूं।

समाजिक सुरक्षा और कल्याण

120. महोदय, हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, विकलांगों और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए बहुत सक्रियता से काम कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 8 लाख 82 हजार लाभार्थियों को 2,000 रुपए से 2,500 रुपए प्रतिमाह की पेंशन दी जा रही है। मैं वर्ष 2023-24 में इसके लिए 2 हज़ार 962 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव करता हूं।

121. मैं समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,744 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूँ।

ऊर्जा

122. माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के हर घर को न्यूनतम बिजली देना उनका अधिकार माना है। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनते ही दिल्ली में प्रतिमाह 400 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले घरों की बिजली की दरें आधी कर दी गईं। कुछ वर्षों के बाद, प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले परिवारों के लिए पूरी तरह से मुफ्त बिजली की व्यवस्था की गई। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। गर्व की बात है कि साल 2022-23 में दिल्ली के 58 लाख 50 हजार घरेलू उपभोक्ताओं में से करीब 84 फीसदी ने इस सब्सिडी योजना का लाभ उठाया है।

123. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। दिल्ली ने 29 जून 2022 को शून्य लोड शेडिंग के साथ 7,695 मेगावाट की अपनी पीक बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। मैं इस सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि दिल्ली में पिछले 8 साल में बिजली के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। साथ ही, कुल AT& C Loss भी घटकर 7 प्रतिशत रह गया है, जो भारत में सबसे कम है।

124. दिसंबर 2022 में, दिल्ली सरकार ने दिल्ली की ड्राफ्ट सौर नीति को अधिसूचित किया। यह नीति सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दिल्ली को देश में अग्रणी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेगी। दिल्ली सौर नीति का लक्ष्य 2025 तक दिल्ली की वार्षिक बिजली की मांग का 25 प्रतिशत सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है, जो वर्तमान में 9 प्रतिशत है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2025 तक 6,000 मेगावाट की क्षमता का सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा। इसमें 750 मेगावाट का 'रूफ टॉप सोलर' शामिल होगा। सौर ऊर्जा नीति का लक्ष्य दिल्ली में हरित रोजगार के लगभग 12 हजार अवसर सृजित करना है। Draft नीति जनता के साथ उनके सुझावों के लिए साझा की गई थी। जनता के सुझावों के आधार पर दिल्ली सरकार अप्रैल 2023 तक नई नीति को अधिसूचित करेगी।

125. दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दिल्ली के बुनियादी बिजली ढांचे को तैयार करने में भी जबरदस्त प्रगति की है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने वाली राज्य की नोडल एजेंसी दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (क्ज्स्) सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में कुशलता से काम कर रही हैं। हम अक्सर देखते हैं कि दुनिया भर के शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की धीमी गति पर्याप्त चार्जिंग स्टेशनों की कमी के कारण है। हमें गर्व है कि दिल्ली सरकार आज सबसे कम दरों वाले EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश कर रही है।

126. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) ने वर्ष 2022-23 में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारत का सबसे बड़ा और पहला पीपीपी मॉडल के आधार पर सफलतापूर्वक टेंडर किया। इसमें 900 ईवी चार्जिंग पॉइंट और 103 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन वाले 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना शामिल है। ये दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों और बस डिपो समेत प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं। EV चार्जिंग के लिए न्यूनतम लागत केवल 3 रुपये प्रति यूनिट है। अर्थात दिल्ली में एक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन का रनिंग कॉस्ट मात्र 7 पैसे प्रति किलोमीटर है, जबकि पेट्रोल स्कूटर के लिए यह 1 रुपया 75 पैसे प्रति

किलोमीटर है। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के लिए यह लागत सिर्फ 8 पैसे प्रति किलोमीटर है, जबकि सीएनजी थ्री व्हीलर पर यह 2 रुपये 62 पैसे प्रति किलोमीटर है। वहीं, चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की रनिंग कॉस्ट सिर्फ 33 पैसे प्रति किलोमीटर है और पेट्रोल से चार पहिया वाहन चलाने पर प्रति किलोमीटर लगभग 7 रुपये खर्च होते हैं। यह किसी क्रांति से कम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अक्टूबर 2022 में 100 ईवी चार्जिंग स्टेशनों में से पहले 11 का उद्‌घाटन कर चुके हैं। अन्य 30 चार्जिंग स्टेशनों का शुभारंभ मार्च 2023 में और बाकी वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुरू किए जाएंगे।

127. मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 3 हज़ार 348 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष जी, अब मैं अपने भाषण का भाग ख प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो राजस्व से संबंधित है।

[भाग ख]

1. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बजट भाषण के पहले भाग में सरकार की नीतियों और योजनाओं की विस्तार से चर्चा की है। अब मैं राजस्व बढ़ाने के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयासों की चर्चा करूंगा।

2. वर्ष 2022-23 (फरवरी, 2023 तक) में GSTऔर VAT के लिए कर संग्रह पिछले वर्ष (फरवरी, 2022 तक) की तुलना में 24.22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 30283.62 करोड़ रुपये रहा।

3. महोदय, हमारी सरकार ने करदाताओं की सुविधा और राजस्व बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रत्येक टैक्स वार्ड में हमने 18 Key Performance Indicators के साथ Monthly Performance Monitoring शुरू की है। व्यापार और कर विभाग सर्वेक्षणों/निरीक्षण/खोज और जब्ती के माध्यम से अपवंचन-रोधी गतिविधियों का प्रभावी ढंग से विश्लेषण और जांच करने के लिए बड़े पैमाने पर GST Analytics और Intelligence Network (GAIN), बिजनेस इंटेलिजेंस एंड फ्रॉड एनालिटिक्स (BIFA) और GST Portal का उपयोग कर रहा है। इसी तरह, वाहनों के अनधिकृत प्रवेश की जांच करने और GST प्रावधानों का उल्लंघन करने पर उन्हें जब्त करने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर भी टीमों को सक्रिय किया गया है।

4. वर्तमान में, व्यापार और कर विभाग ने उन करदाताओं के लिए E-Invoice अनिवार्य करना शुरू कर दिया है, जिनका कुल कारोबार 10 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा, व्यापार और कर के प्रत्येक वार्ड के शीर्ष 200 करदाताओं का नियमित विश्लेषण और अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

5. फर्जी/गैर-मौजूद फर्मों द्वारा Tax Evasion पर अंकुश लगाने और उन पर निगरानी के लिए एक नए वार्ड 210 के रूप में Fake Firm Cell का गठन किया गया है। यह Cell

हाई मिस-मैचिंग, अन्य राज्यों द्वारा संदर्भित कंपनियों, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि के बारे में प्राप्त सूचना व इनपुट पर कार्रवाई करता है।

6. विभाग ने GST से बाहर के पात्र करदाताओं को कर के दायरे में लाकर Tax Base बढ़ाने के लिए कई outreach कार्यक्रम आयोजित किए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक outreach कैंपों के माध्यम से बाजार और व्यापार संघों के साथ लगभग 200 बैठकें की जा चुकी हैं। जमीनी स्तर से मिले फीडबैक से भविष्य की कर नीतियों को आकार देने में मदद मिलेगी।

7. करदाताओं के दस्तावेज़ों के प्रमाणीकरण की जांच करने के लिए Document Identification Number (DIN) उत्पन्न करने से संबंधित सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन को अमल में लाया गया है। GST विभाग ने जनवरी 2023 से इसे लागू कर दिया है। अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में इसे लागू करने वाला दिल्ली देश का तीसरा राज्य है।

8. महोदय, हमारी सरकार का इरादा अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक समर्पित Tax Policy and Revenue Augmentation Unit का संचालन शुरु करना है। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य अवसरों की पहचान, Revenue Leakages का पता लगाना और नीति निर्माण में विभाग की सहायता करके राजस्व में वृद्धि करना है।

9. दिल्ली सरकार आबकारी राजस्व में वृद्धि और प्रभावी तरीके से उत्पाद विनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार Faceless Enforcement और Excise Intelligence Bureau को मजबूत करने जैसे उपायों के जरिए शराब के अवैध कारोबार से मुक्ति सुनिश्चित करने और समूचे शहर में गुणवत्ता युक्त शराब सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है।

10. सरकार ने सितम्बर 2022 से उत्पाद शुल्क आधारित व्यवस्था बहाल कर दी है। Hospitality उद्योग (Hotel, Clubs, Restaurants आदि) रोजगार मुहैया कराने, tax generation और पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने

में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सरकार शराब आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली की मौजूदा तकनीक को बढ़ाने और उन्नत करने के लिए नई तकनीक विकसित करने पर काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय मैं अपने बजट भाषण का समापन मशहूर शायर अशोक साहिल की इन पंक्तियों से करना चाहूंगा-

नजर नजर में उतरना कमाल होता है,

नफस नफस में बिखरना कमाल होता है।

बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं,

बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है।